मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

खोदा पहाड़ निकाली चुहिया	3
मुस्लिम सदस्यों ने भाजपा छोड़ी	4
नेटबंदी से कश्मीर हुआ दोजख	5
गिलानी को याद रखा जाये	6
केजरीवाल के काम की छाप	8

वर्ष 33 अंक 11 फ़रीदाबाद 26 जनवरी-1 फ़रवरी 2020 फोन -8851091460 2.₹०

शहर में फूड सैंपलिंग बना लूट का धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) जनता को मिलावट रहित एवं शुद्ध खाने-पीने को मिलता रहे, इसके लिये सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एक फूड इन्स्पेक्टर का पद बनाया था, जो ज़िले के सीएमओ के अधीन काम करता था। सीएमओ के कमाऊ पूतों में से एक बड़ा कमाऊ पूत फूड इन्स्पेक्टर भी हुआ करता जो खाने-पीने के सामान बनाने व बेचने वालों से अच्छी-खासी उगाही किया करता था।

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएमओ की इस लूट-कमाई को बंद करने के लिये फूड इस्पेक्टर का पद समाप्त कर अलग से एक प्राधिकरण (अथॉरिटी) बना दी। इसके तहत हर ज़िले में एक डीओ और उसके अधीन एक डेजिग्नेटिड ऑफ़िसर व उसके आधीन एक एफएसओ (फूड सैंपलिंग ऑफ़िसर), एक असिस्टेंड यानी बाबू और एक डाटा इंट्री ऑप्रेटर नियुक्त कर दिया गया। इस स्टाफ़ का सीएमओ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सीधे चंडीगढ स्थित प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

विज की इस नई व्यवस्था के तहत फ़रीदाबाद में एनडी शर्मा बतौर डीओ तैनात है जो पहले फूड इन्स्पेक्टर हुआ करता था। यह द्वितीय श्रेणी का पद है। इसके आधीन एक सरकारी डॉक्टर आदित्य चौधरी बतौर एफ़एसओ तैनात है। डॉक्टर का पद प्रथम श्रेणी का होता है लेकिन जब लूट-कमाई ही करनी हो तो पद और श्रेणी का क्या देखना, किसी तरह जुगाड़बाज़ी लगा कर इस पद को हथिया लिया जाता है। इस पद पर दोहरा मज़ा यह है कि न तो किसी दफ़्तर में हाजिरी देनी है न कोई काम करना है, बस घर बैठे लूट-कमाई का हिस्सा चुप-चाप मिल जाता है।

मंत्री अनिल विज : फूड सैपलिंग का बन्द दफ्तर सिर्फ लूट का हिसाब रखने के लिए खुलता है

असिस्टेंट के पद पर तैनात राजीव कुमार इसी महकमे में चपरासी से क्लर्क और पदोन्नत होकर असिस्टेंट हो गया। इसका जोड़ीदार मनिंदरपाल सिंह डाटा इन्ट्री ऑप्रेटर ठेकेदारी पर है। इसके काले कारनामों की लिस्ट जब सिरसा में बहुत लम्बी हो गयी थी तो इसे ब्लैक लिस्ट कर काम से हटा दिया गया था; परन्तु राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जुगाड़बाज़ी के चलते यह न केवल काम पर बहाल हो गया बल्कि लूट-कमाई में नम्बर वन ज़िला फ़रीदाबाद में तैनात हो गया।

इन दोनों की जोड़ी के पास अपनी एक निजी स्विफ्ट कार है जिस पर अवैध रूप से अंग्रेजी में लाल पेंट से लिखा है, ''गवर्मेंट ऑफ़ हरियाणा'' इन दोनों की जोड़ी अपने दोनों अफ़सरों के आशीर्वाद से बाज़ारों में सैंपल भरने का डरावा दिखा कर दिन भर अवैध वसूली करने में जुटे रहती हैं।

नियमानुसार इन दोनों को तो बीके अस्पताल स्थित अपने दफ़्तर में बैठना चाहिये तथा ऊपर के दोनों अधिकारियों को दिनचर्या यानी मूवमेंट रजिस्टर में भर कर बाज़ारों में निकलना चाहिये तथा सही ढंग से खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट की रोक-थाम करनी चाहिये, जो ये नहीं करते। कानूनन डीओ अपने हस्ताक्षर से स्लिप जारी करता है जो लिये गये सैंपल पर चिपकाई जाती है। केवल एफ़एसओ सैंपल लेने को अधिकृत होता है। परन्तु मिलीभगत के चलते डीओ अपने असिस्टेंट को ही कोरी स्लिप हस्ताक्षर कर के दे देता है जिसके बल पर यह जोड़ी फरीदाबाद से पलवल व नूह तक धमाल मचाती है।

प्रति माह 30 सैंपल भर कर लैबोरेट्री भेजने की औपचारिकता ये लोग जरूर पूरी करते हैं। ताकि नौकरी कायम रह सके। इस काम में भी ये लोग दुनिया भर की जुगाड़बाज़ी करते हैं। ऐसे डिब्बाबंद सैंपल लेंगे जो पास होने ही होते हैं लेकिन उनको पास कराने के नाम पर अच्छी-खासी वसूली कर लेते हैं।

वैसे कम तो लैबोरेट्री में बैठे घाघ भी नहीं हैं। वे अच्छे-खासे पास होने वाले सैंपल को फ़ेल तथा फ़ेल होने वाले को पास करने का धंधा खुलेआम चला रहे हैं।

इसी महकमे में एक कर्मचारी ने अनजाने में इस संवाददाता को बताया कि उन्हें न केवल ज़िले भर के प्रशासनिक अधिकारियों की फ़टीकें भुगतनी पड़ती हैं बल्कि सम्बन्धित न्यायिक मैजिस्ट्रेट की फटीक भी करनी पड़ती है।

फ़रीदाबाद नगर निगम कर चोरों पर तो कार्यवाही लेकिन कामचोरों और रिश्वतखोरों को छूट

फ़रीदाबाद (म.मो.) फ़रीदाबाद नगर निगम ने कर चोरों के खिलाफ़ पिछले करीब तीन माह से अभियान छेड़ा हुआ है। निगम के अनुसार शहर के विभिन्न बकायेदारों पर लगभग 220 करोड़ रुपये का सम्पत्ति कर बकाया है। इसमें 150 करोड़ रुपये उद्योगों और कमर्शियल भवनों पर बकाया है। करीबन दस हज़ार लोग ऐसे हैं जिन पर 50 हजार रुपये से ज्यादा सम्पत्ति कर बकाया है। निगम अभी तक ऐसे 15000 कर चोरों को कर जमा करने का नोटिस भेज चुका है तो 300 भवनों को अभी तक सील कर चुका है।

31 जनवरी तक भी जो लोग कर नहीं जमा करायेंगे निगम उनकी सम्पत्ति कुर्क करके नीलाम करने की योजना बना रहा है ताकि वह अपने सम्पत्ति कर की राशि उनसे वसूल सके। निगम ने 31 जनवरी तक ब्याज माफ़ी योजना भी चलाई हुई है जिसके तहत 2010 से बकाया सम्पत्ति कर एकमुश्त जमा करवाने पर कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लिया जायेगा। बता दें कि पिछले हफ्ते निगम का दस्ता एस्कार्ट ग्रुप के मथुरा रोड स्थित कॉरपोरेट ऑफ़िस को भी सील करने पहुंचा था लेकिन सिर्फ़ उनके सामने रिरियाकर वापिस लौट गया। एस्कॉर्ट ग्रुप पर कई करोड़ रुपये सम्पत्ति कर बकाया है।

निगम अपने पैसे वसूल करने को तो पूरा तत्पर है लेकिन उस पैसे के बदले उसे जो सेवायें देनी चाहिये उनके बारे में पूरी तरह चुप है। जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुये हैं। 15 सेक्टर जैसे पॉश सेक्टर में भी सीवर जाम पड़ा रहता है। रोड टूटे पड़े हैं। स्ट्रीट लाइट की कोई ठीक व्यवस्था नहीं। पानी का कोई ठीक प्रबंध नहीं। अभी तक पानी की 'बिलिंग' को निगम कम्प्यूटराईज नहीं कर पाया है जिसके चलते उसे करोड़ों रुपये साल का नुक्सान हो रहा है जबकि उसके कर्मचारी मोटी रिश्वतें खा रहे हैं। विज्ञापन बोर्ड लगाने और पार्किंग के ठेके देने में भयंकर भ्रष्टाचार है। निगम अपने इन कामचोर और रिश्वतखोर कर्मचारियों को यदि सीधा कर दे तो उसका कायापलट हो सकता है। लेकिन शायद इस लूट की छूट बहुत ऊपर से ही मिली हुई है इसलिये कुछ दिखावटी अभियान चलाने के अलावा निगम के पल्ले कुछ नहीं है।

मोदी सरकार का ईएसआई निगम कर रहा मज़दूरों के जीवन से खिलवाड़

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में सुधी पाठको ने पढा था कि एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मज़दूरों की देख-भाल के लिये नर्सिंग स्टाफ़ की कितनी भारी कमी है। जहां 6 मरीज़ों की देखभाल के लिये एक नर्सिंग स्टाफ़ होना चाहिये वहां 26 पर एक लगा है। ऐसे में मरीज़ों के भाई-बंधु दिन-रात बैठ कर अपने मरीज़ों की देख-भाल करते हैं। लेकिन जो मरीज़ अति गंभीर हालत में होते हैं उन्हें अपने भाई-बंधुओं की देख-रेख के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे मरीज़ों को साधारण वार्ड की बजाय आईसीयू (गहन देख-रेख इकाई) में रखा जाता है।

राज्य भर के किसी भी ईएसआई अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था न होने के चलते ऐसे मरीज़ों को निजी व्यापारिक अस्पतालों में रैफ़र कर दिया जाता था जो मरीज़ों से भी (डरा-धमका) वसूली करते थे और ईएसआई से भी करोड़ों रुपये के बिल प्रति वर्ष वसूलते थे। रैफ़रल बिलों के भारी-भरकम भुगतान से बचने के लिये चाहिये तो यह था कि, अपनी आवश्यकता को देखते हुए, निगम अपने अस्पतालों में निजी अस्पतालों से भी बेहतर आईसीयू का निर्माण करता; परन्तु उस पर होने वाले खर्च को बचाने के लिये निगम ने मात्र 30 बेड का एक छाटा सा आईसीयू अपने इस एनएच-तीन वाले अस्पताल में एक ठेकेदार से खुलवा दिया।

जाहिर है ठेकेदार यहां कोई पुण्य कमाने तो आया नहीं था, आधी-अधूरी सेवाऐ देने के बावजूद भी जब उसे मुनाफ़े की जगह घाटा होने लगा तो वह छोड़ भागा। और भागा भी ऐसा कि उस यूनिट को ताला लगा गया जिसे निगम दो घंटे में भी खुलवा नहीं सका।

इसके बंद होते ही फ़िर रैफ़रल बिलों के बढ़ने की समस्या से बचने के लिये निगम ने मरीज़ों को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की ओर धकेलना शुरू किया। कुछ प्रभावशाली मरीज़ों को स्थानीय निजी अस्पतालों में भी भेजा जाने लगा।

करीब साल भर के इस ड्रामे के बाद इसी अस्पताल में 20 बेड की एक नकली सी आईसीयू बनाई गयी। जहां 100 बेडेड आईसीयू की जरूरत हो वहां 20 बेड वाली तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और नकली इसलिये कि 20 बेड पर जहां 70 नर्स व 5 विशेषज्ञ डॉ. हर वक्त रहने आवश्यक हैं वहां केवल 20 नर्स ही तैनात हैं। जाहिर है कोई भी नर्स 24 घंटे पूरा सप्ताह तो तैनात रह नहीं सकता। इस लिये यहां आवश्यकता है 70 नर्सों की और डॉक्टर भी एनेस्थिसिया व मेडिसन के होने चाहिये। परन्तु जब पूरे अस्पताल में ही 40 अनेस्थिसिया डॉक्टरों की जगह कुल 12 डॉक्टर हों तो आइसीयू में लगाने को कहां से आयेंगे?

लगभग यही स्थिति मेडिसन विभाग के डॉक्टरों की हैं। इन हालात में आइसीयू में डाले जाने वाले मरीजों से पिंड छुड़ाने के लिये उन्हें दिल्ली के लिये रैफ़र करके एम्बुलेंस में डाल कर एम्स या सफ़दरजंग मे धकेल दिया जाता है जहां पहले से ही हाउसफुल चल रहा है। समर्थ मरीज़ किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज कराता है और असमर्थ मौत को गले लगाता है।

यहां गौरतलब बात यह है कि मोदी सरकार एक ओर तो बीते ढाई वर्षों से, चिकित्सा के नाम पर आयुष्मान का ड्रामा खेलने में जुटी है वहीं दूसरी ओर मज़दूरों के वेतन से साढे छः प्रतिशत की वसूली कर लाखों करोड़ के खजाने पर कुंडली मार कर भी मज़दूरों को वांच्छित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से हाथ खींच रही है।

तुर्की-ब-तुर्की : आईएएस अशोक खेमका

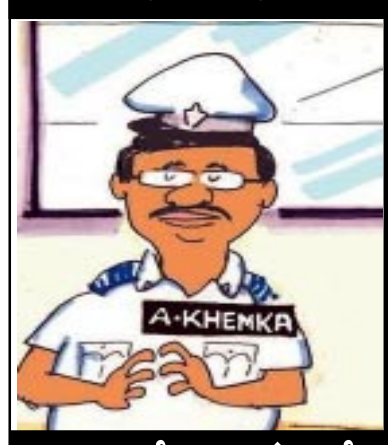

आईएएस इंचार्ज

सरकार को चिट्ठियां लिखकर असहज करने की कला में पारंगत आईएएस अफसर अशोक खेमका ने अपनी नई चिट्ठी में आईएएस को सर्वश्रेष्ठ बताकर स्वयं को भी असहज करने वाली बातें कर डाली हैं। इससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, सिवाय आईएएस लॉबी के।

आईएएस एसोसिएशन अब एक प्रस्ताव के जरिए अपनी जानकारी के लिए खेमका से उन उपलब्धियों की लिस्ट मांगने जा रही है जिनके चलते उन्हें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।